श्री राजनारायण मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या शौलामारी आश्रम के संबंध में सरकार के पास पूरी जानकारी है ? अगर नहीं है, तो क्या सरकार इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री सभापति उन्होंने कहा है कि हम इन्क्वायरी कर रहे हैं और मालूम करके सब चीजें हाउस को बतलायेंगे ।

श्री राजनारायण सरकार ने तो इन्कम टैक्स के बारे में कहा है । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इसकी जानकारी मुझे अच्छी है ।

श्री सभापति तो आप बतला दें ।

श्री राजनारायण यह जो सारा फ्राड हो रहा है वह सरकार की जानकारी में हो रहा है और सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करती जिसके जरिये शौलामारी आश्रम के साधु के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती । इस साधु द्वारा जिले जिले में बड़ा चन्दा इकट्ठा हो रहा है ।

श्री सभापति उन्होंने अभी कहा है कि इस बारे में खत आये हैं और उसके बारे में मालूम किया जा रहा है । जब रिपोर्ट आ जायेगी तो बतला दिया जायेगा ।

SHRI LOKANATH MISRA : Since there is also a suspicion in the country that since this particular area belongs to the border, there is some possibility of some espionage under the garb of an Ashram, may I know whether the Finance Ministry would get a report from the Home Ministry before examining this particular case of exemption from income-tax ?

SHRI L N MISHRA : I would send all the proceedings, concerning this question, of this House to the Home Ministry.

SHRI R. S. KHANDEKAR : May I know how the C.I.B. comes into the picture in an Income-tax case ? The Income-tax Department has its own machinery to investigate the cases and what were they doing so long when there were allegations and when it was a known fact that a lot of expenditure was going on in that Ashram ?

SHRI L. N. MISHRA : I never said C I B I said the Commissioner of Income-tax

SHRI BHUPESH GUPTA : Since the Shoulamari Ashram is not a registered body, all the money or income available to it should be treated as a personal income, in the present case, of the Sadhu—whatever he is, whether he is a Sadhu or Asadhu, I am not concerned with it. May I know whether any notice has been served on him by the Income-tax authorities in view of the fact that these are notoriously known facts that a lot of money is being spent in this Ashram and whether it is not a fact that some politically disgruntled people and certain others who want to flourish by using the name of Netaji Subhash Chandra Bose and so on are clustering round that Ashram and getting all kinds of things done there ? I would like to know why the Government is so lenient in this matter when under the Income-tax Act they are empowered to serve notice on such people whose personal income is liable to be taxed and it is a case of personal income ?

SHRI L. N MISHRA : We are not lenient. The matter has been brought to our notice We have ordered a full probe into this matter and it will be enquired into and we have not shown any concession simply because he is a Sadhu or somebody else A regular enquiry would be made

भारतीय तथा पाकिस्तानी बैंक

*822 **श्री रघुनाथ प्रसाद खेतान** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले भारत-पाक संघर्ष से पहले पाकिस्तान में भारतीय बैंकों की कुल कितनी ब्राचें थीं और भारत में पाकिस्तानी बैंकों की कुल कितनी ब्राचें थीं,

(ख) पाकिस्तान में भारतीय बैंकों और भारत में पाकिस्तानी बैंकों की परिसम्पत्तियों का ब्योरा क्या है,

(ग) इस समय पाकिस्तान स्थित भारतीय बैंकों में कितने कर्मचारी हैं, और

(घ) दोनों देशों में बैंकों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

†[INDIAN AND PAKISTANI BANKS

*822. SHRI R. P. KHAITAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what was the total number of branches of Indian banks in Pakistan and the total number of branches of Pakistani banks in India before the last India-Pakistan conflict;

(b) the details of the assets of Indian banks in Pakistan and of Pakistani banks in India,

(c) the present number of employees in Indian banks in Pakistan; and

(d) what efforts are being made for the proper functioning of banks in both the countries ?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) सितम्बर 1965 से पहले, 17 भारतीय बैंकों की 40 शाखाएं पाकिस्तान में थी जिनकी परिसम्पत्ति 22.79 करोड रुपया और देनदारी 21.48 करोड रुपया थी।

दो पाकिस्तानी बैंकों की दो शाखाएं भारत में थी जिनकी परिसम्पत्ति 1.99 करोड रुपया और देनदारी 1.96 करोड रुपया थी।

(ग) पाकिस्तान-स्थित भारतीय बैंकों में अब कोई भारतीय कर्मचारी नहीं है। एक को छोड, बाकी सभी भारतीय कर्मचारी भारत लौट आये है।

(घ) इन बैंकों के कामकाज के फिर से चालू किये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध, भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों के सामान्य स्थिति में आने के व्यापक प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) and (b) Prior to September, 1965, 17 Indian banks had 40 branches in Pakistan with assets amounting to Rs. 22.79 crores and liabilities amounting to Rs. 21.48 crores.

Two Pakistani banks had two branches in India, with assets amounting to Rs. 1.99 crores and liabilities amounting to Rs. 1.96 crores.

(c) There are no Indians in employment in the Indian banks in Pakistan now, all India-based employees, with one exception, having since returned to India.

(d) The resumption of the activities of these banks is linked with the general question of the normalisation of Indo-Pakistan relations.]

श्री रघुनाथ प्रसाद खेतान : अभी कितने बैंकों के ब्राच वहा पर काम कर रहे ह ?

श्री बी० आर० भगत : अभी तक तो वहां पर करीब 40 बैंकों के ब्राच काम करते थे, लेकिन अब तो कोई ब्राच वहां पर काम नहीं करता है। जैसा मैंने कहा : The resumption of the activities of these banks is linked with the general question of the normalisation of Indo-Pak relations.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बैंकों का सामान्य कार्य चलना भारत और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों पर निर्भर करता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सम्भावना है निकट भविष्य में कि जो हमारा आर्थिक सबंध राजनैतिक संबंध से जुडा हुआ है वह अच्छे हो जायंगे और ये बैंक वहा पर अपना कार्य करने लग जायेंगे ? अगर ऐसी सम्भावना नहीं है तो हमेशा के लिए इन बैंकों को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है ?

श्री बी० आर० भगत : हमारी हमेशा यही उम्मीद रहती है कि हमारे और पाकिस्तान

†[ ] English translation.

के साथ संबंध अच्छे हों और दोस्ताना रहें। इसलिए ऐसी स्थिति में इस तरह का प्रयास करना और यह मानकर चलना कि भविष्य में हम कोई बैंकिंग का काम वहां पर नहीं करेंगे, ठीक नहीं है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : जैसा कि श्रीमान् ने अभी अपने उत्तर में बतलाया कि वहां पर कोई भी भारतीय कर्मचारी इन बैंकों में काम नहीं कर रहा है।

एक माननीय सदस्य : एक कर्मचारी है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : एक कर्मचारी तो नैगलिजबल है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जो रकम भारतीय बैंकों को वहां के लोगों से लेनी है वह अवधि से बाहर हो जाने वाली है, तो इसके लिए क्या उच्चस्तरीय वार्ता का कोई प्रावधान किया जा रहा है कि जबतक अपने झगड़े का सैटिलमेंट नहीं हो जाता तबतक उसकी अवधि खत्म नहीं होगी ?

श्री बी० आर० भगत : कैसी अवधि ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अगर कोई पैसा उधार लेना है तो उसको तीन साल के अन्दर वसूल कर लेना चाहिये। अगर इस झगड़े के अन्तर्गत कोई समझौता नहीं होता है तो तीन साल का अवधि खत्म हो जाती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अवधि को बढ़ाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिये क्योंकि तीन साल की मुद्दत हो जाने के बाद भी भारतीय बैंक अपना रुपया वसूल कर सकेंगे और इसमें वहां की सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ?

श्री बी० आर० भगत : यह बात तो भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से आर्थिक संबंधों का होना और सामान्य स्थिति पैदा होने पर निर्भर करता है। हम पाकिस्तान सरकार पर जोर दे रहे हैं कि जहां तक बैंकों की जिम्मेदारी है, ओब्लीगेशन्स हैं, वह उनमें चले और उनके लिए उचित स्थिति होना चाहिये। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय हितों की रक्षा होनी चाहिये। इसमें यह भी आता है कि जो बैंकों की लेनदारी है उसको वह वापस ले सकें। इस तरह से सभी बातों का संबंध है।

SHRI G. MURAHARI : I would like to know from the Government whether, during the signing of the Tashkent agreement, questions of this nature were also discussed, especially the functioning of banks and other such matters and, if not, whether the Government intends raising this question on the basis of the Tashkent agreement, because several other questions like civil aviation, and other things have been discussed. So I would like to know why the Government is delaying this particular matter.

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, the Government of India is not delaying in this particular matter. It requires both India and Pakistan . . .

SHRI G. MURAHARI : Are you taking the initiative ?

SHRI B. R. BHAGAT : It is known to the hon. Members that resumption of economic relations and trade relations was also a part of the Tashkent agreement, and a meeting took place immediately after that. There is also the talk of another meeting and we hope that probably the meeting will take place. Then some of these questions may also be raised.

SHRI BHUPESH GUPTA : There does not seem to have been a proper approach in regard to this matter. Now the National Bank of Pakistan has a number of Indian employees, Indian citizens, and they are getting their salaries all right but, at the same time, the employees of the Pakistan International Airlines and so on, they are not getting, the Indian citizens who are the employees are not getting similar salaries for months and months, since the trouble started. Although the whole thing is now supposed to be under the

Custodian, under the Government of India, how is it that the Finance Ministry is not taking up with the other Pakistani concerns employing Indian citizens here that, like the National Bank of Pakistan, they too should give salaries to their employees, other Pakistani concerns like the Pakistan International Airlines, who have a number of Indian employees here but who have not given the Indian employees, the Indian citizens, any salary, as I said.

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, in the National Bank of Pakistan there were 57 Indian employees and in another Pakistani bank, the Habib Bank Limited, 43 employees were Indians. Most of the Indian employees of the latter bank have been served with retrenchment notices. So the Custodian of Enemy Property and the Reserve Bank have written to certain scheduled banks in the Bombay area to consider their cases sympathetically and provide employment to such of them as are found suitable.

MR. CHAIRMAN : Next question.

PRINTING OF NOTES OF SMALLER SIZE

*823. SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state how much imported paper will be saved in quantity and in terms of foreign exchange as a result of the reduction in the size of the existing currency notes ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI L. N. MISHRA) : The quantity of paper that would be saved annually as a result of reduction in size of notes is estimated to be a little over 300 tonnes. The savings in foreign exchange cost would be of the order of Rs. 30 lakhs annually.

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE : Sir, we welcome the Government's economy measure to save on imports but is it true, I like to know, that now, after Devaluation, the Government is giving licences to some industrialists for importing raw materials without levying any precondition for export of the finished articles manufactured from those imported materials ? I shall like to know, Sir, whether the Government is allowing imports from the point of view of lowering the internal prices. If so, has the Government taken any assurance from those manufacturers that the prices will not be raised ?

SHRI L. N. MISHRA : Sir, the question relates to printing of notes of a smaller size. The supplementary question put has nothing to do with it.

MR. CHAIRMAN : It is about paper for currency notes.

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE : But imported material is involved in this and it will decrease our foreign exchange resources. That is why I put the question.

MR. CHAIRMAN : It is much more a general question.

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : सभापति महोदय, सरकार ने छोटे नोट छापने का जो फैसला किया है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नोट छापने के पहले क्या सरकार पूरी तरह से इस बात की जानकारी जनता को दे देगी जिससे कि देहात में रहने वाले अनपढ़ और गरीब लोग उन नोटों के छापने से कहीं परेशानी में न पड़ जायं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : होना ही चाहिये, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा दोनों के साइज़ में । इसमें थोड़ा सा मामूली फर्क होगा । फिर भी इसका प्रचार होना है और इसका प्रबन्ध अच्छी तरह से किया जाता है ।

SHRI P. K. KUMARAN : May I know, Sir, what kind of reduction in size is contemplated as far as the currency notes are concerned that is one thing, and another—while calculating the surplus of paper, whether the large number of counterfeit notes that are in circulation, whether that surplus also will be taken into consideration ?